eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

वर्तमान दौर में भारत अमेरिका सम्बन्ध

डॉ0 प्रियंका त्रिपाठी[1]
[1]शोधार्थी– राजनीति विज्ञान, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर उ0प्र0

Received: 21 Jan 2026 Accepted & Reviewed: 25 Jan 2026, Published: 31 Jan 2026

Abstract

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत अमेरिका सम्बन्ध रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों में निरंतर परिवर्तन और गहराई आई है। 21वीं सदी में भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में सामने आया है, जबकि अमेरिका विश्व की अग्रणी महाशक्ति बना हुआ है। साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, रक्षा सहयोग, व्यापार निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है। हालाँकि, व्यापार असंतुलन, वीज़ा नीति, मानवाधिकार, और रणनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दे दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। इसके बावजूद, समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु भारत अमेरिका साझेदारी भविष्य में और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना रखती है। यह अध्ययन वर्तमान दौर में भारत अमेरिका संबंधों के प्रमुख आयामों, अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द– भारत अमेरिका सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, इंडो–पैसिफिक, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, वैश्विक राजनीति, रणनीतिक स्वायत्तता

Introduction

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ जो भी सम्बन्ध होते हैं वह केवल राष्ट्रीय हित पर ही आधारित होते हैं। स्वतन्त्र होने के बाद भारत को खुद को स्थापित करने हेतु यह आवश्यक था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत स्थिति में लाये और इसके लिए आवश्यक था वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ अपने सम्ब्न्ध मजबूत करें तो भारत ने ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के साथ अपने सम्बन्ध को बेहतर करने पर कार्य करना आरम्भ किया। लेकिन अगर अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों की बात करें तो आरम्भ से ही यह सम्बन्ध मधुरता के स्तर पर नहीं थे। नेहरु जी और इन्दिरा गाँधी जी दोनों लोगों के प्रधानमन्त्री काल में अमेरिका और भारत के सम्बन्ध एक प्रकार से आवश्यकता पूर्ति के थे नेहरु जी ने अमेरिकी शीत युद्ध की तीखी आलोचना की और वैश्विक शान्ति के लिए तीन स्तरों की बात की वह कहते हैं कि दुनिया दो देशों में बँटी है जिससे तीन गम्भीर समस्यायें हमारे सम्मुख है– 1. उपनिवेशवाद, 2. श्वेत वर्चस्व, 3. भूखमरी

अब नेहरु जी के इस बात से स्पष्ट है कि वह अमेरिकी नीतियों के प्रति किस तरह की सोच रखते थे। अमेरिका के प्रति नेहरु जी का स्पष्ट मानना था कि भारत को कुछ हद तक अमेरिका के साथ गठबन्धन में रहना चाहिए लेकिन अमेरिका के अधीन नहीं यहाँ यह बात स्पष्ट है कि भारत अमेरिका के साथ बराबरी चाहता था उसकी अधीनता नहीं। तो यह कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भारत के सम्बन्ध शीत युद्ध काल में अनिश्चिता के थे जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद भारत अमेरिका सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये। तो तब से लेकर आज तक ऐसा दौर कभी नहीं दिखा जिससे ये कहा जा सके कि भारत अमेरिकी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

सम्बन्ध मधुरता वाले रहे हैं। हाँ यह जरुर है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ बनाता है ऐसे ही भारत ने अमेरिका के साथ अपने सम्म्बन्धों में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। अगर हाल की बात की जाए तो अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगा दिया क्योंकि भारत रुस से तेल खरीद रहा और यह अमेरिका का भारत पर बहुत बड़ा दबाव था लेकिन भारत ने यहाँ भी अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका के इस रूख को नजर–अन्दाज कर चाइना और रूस के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी पर कार्य करने लगा और अमेरिका को यह दिखाने का प्रयास किया कि उसके राष्ट्रीय हित किसी भी शक्तिशाली देश के दबाव से ऊपर है।

भारत अमेरिका सम्बन्ध इतिहास के पृष्ठभूमि में – सन् 1949 में नेहरु अमेरिका की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमन्त्री बने उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी टूमैन थे इसके बाद नेहरु जी ने सन् 1956, 1960 और 1961 में अमेरिका की यात्रा की यह वह दौर था जब भारत ने तटस्थता की घोषणा की और गुटनिरपेक्षता का समर्थन करने वाला देश बना पूरे शीत युद्ध काल में भारत के सम्बन्ध रुस के साथ जरुर मधुर बने रहे लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। भारत–अमेरिका के सम्बन्ध कैसे रहे इसका प्रमाण कई बार अमेरिका के अपने खुद की हरकतों से दिया। सन् 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका जरुर निभाई लेकिन सहयोग उसने पाकिस्तान को दिया। बात यहाँ पाकिस्तान सहयोग की नहीं बात यहाँ इस भूमिका की हो रही कि अगर अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है तो जरुर उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वह गलत को गलत कहे और इतिहास प्रमाण है इस बात का कि अमेरिका ने हमेशा सही गलत, उचित अनुचित नैतिकता अनैतिकता के बीच केवल अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा।

भारत की आरम्भ से ही सोच किसी भी देश के पीछे चलने की नहीं थी वह हमेशा खुद को नेतृत्वकर्त्ता के रूप में देख रहा था अतः उसने कभी भी अमेरिका के पीछे चलने की नीति का पालन नहीं किया है ये जरुर था कि भारत ने अब सशक्त देशों की भाँति खुद के राष्ट्रीयहित को सर्वोपरि रखा और यह शिक्षा कहीं न कहीं उसने अमेरिका से लिया जैसे भारत ने सोबियत संघ के साथ 20 साल के लिए सहयोग संधि किया जो गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुपालन नहीं था और फिर 1974 में परमाणु परीक्षण के साथ भारत संयुक्त सुरक्षा परिषद के पाँच सदस्यों के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बना और इसी परमाणु परीक्षण की वजह से भारत अमेरिका सम्बन्ध दो देशकों तक अच्छे नहीं थे।

सन् 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत की यात्रा पर आते हैं तब देसाई प्रधानमन्त्री थे और कार्टर ने परमाणु अप्रसार अधिनियम की बात की और भारत सहित कई देशों के परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की माँग की और भारत ने इस कार्य हेतु सीधे इंकार कर दिया तो अमेरिका ने भी भारत के साथ सभी परमाणु सम्बन्ध खत्म कर दिया।

इस प्रकार इतिहास के पन्नों में भारत अमेरिका के सम्बन्ध खींच–तान वाले रहे। सन् 1984 में भोपाल काण्ड के बाद ये रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो गया। सन् 1984 में अमरीकी कम्पनी यूनियन काबाईड में रिसाव हुआ हजारों लोगों की मौत हुई और भारत ने इस कम्पनी के सी0ई0ओ0 के भारत में प्रत्यर्पण का प्रयास किया जिससे द्विपक्षीय रिश्ते और भी तनाव पूर्ण हो गये। हाँ 1991 में वह दौर था जब भारत में आर्थिक, उदारीकरण आया तब उस दौर में भारत अमेरिकी सम्बन्ध में आवश्यक सुधार देखने को मिले लेकिन सन् 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद फिर से भारत व अमेरिका के सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

सन् 2000 में अमेरिकी की राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच ऊर्जा और पर्यावरण पर समझौता हुआ। इसके बाद 1999 में करगिल संघर्ष के दौरान क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ को वाशिगटन बुलाया फिर पाकिस्तान ने अपनी सेना को नियन्त्रण रेखा से पीछे हटाया और 2001 में प्रशासन ने आर्थिक प्रतिबन्ध हटाया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आजादी के बाद जब भारत सभी स्तर पर संघर्ष कर रहा था तो भी उसने अमेरिका के गलत नीतियों का समर्थन नहीं किया फिर चाहे वह शीत युद्ध हो या परमाणु अप्रसार की नीति हो या परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत के प्रति अमेरिका का नकारात्मक रुख हो भारत ने कभी भी न तो अमेरिकी दबाव में आकर कोई कार्य किए और न ही अमेरिका का गलत नीतियों में समर्थन किया और जब धीरे–धीरे भारत इस स्थिति में आ गया कि विश्व स्तर पर उसकी स्थिति विकासशील देशा में भी उच्चतर की हो गयी तो अमेरिका को अपना रुख उसके प्रति मजबूरी में नरम करना पड़ा। अमेरिका ने आरम्भ से ही पाकिस्तान में अपनी रुचि दिखायी क्योंकि चाइना की तरह वह भी इस बात में विश्वास रखता है कि भारत को अपनी प्रगति से इतर अगर कहीं मजबूर किया जा सकता है तो वह केवल पाकिस्तान के जरिये इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के लिए अपना रुख नरम रखता है। भारत ने आरम्भ से ही अमेरिका के इस रवैया को समझा लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राष्ट्र न तो आपस में शत्रु है और न ही मित्र है केवल राष्ट्रीय हित प्रमुख है और भारत ने शक्तिशाली राष्ट्रों की भाँति अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा जैसे गुट निरपेक्षता की नीति किसी भी खेमे में नहीं जाने की थी लेकिन भारत ने रुस के साथ 20 वर्ष का सहयोग सम्बन्ध स्थापित किया इसी प्रकार बिना अमेरिकी नीति की परवाह किए भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अप्रसार नीति का विरोध किया। अमेरिका आरम्भ से ही यह चाहता था कि भारत अमेरिका के पीछे चलने वाला राष्ट्र बने लेकिन भारत ने जैसा कि नेहरु जी ने कहा था कुछ गठबन्धन अमेरिका के साथ किया जा सकता है पर अमेरिका की अधीनता को भारत स्वीकार नहीं करेगा तो आज तक अपने वैदेशिक नीति ने भारत ने नेहरु जी के इसी कथन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पालन किया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को देखते हुए धीरे–धीरे अमेरिका को अपने रुख में परिवर्तन करना पड़ा और अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ भारत का व्यवहार हमेशा समकक्ष जैसा था भारत ने कभी भी अमेरिका के किसी नीति का समर्थन इसलिए नहीं किया कि अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है तो अमेरिका में हर उचित अनुचित में भारत हामी भरेगा। जिस तरह से अमेरिका को राष्ट्रीय हित सर्वोपरि लगता है वैसे भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और इस प्रकार अमेरिका और भारत में विभिन्न सहयोग स्तर पर वार्ता और समझौते का दौर आरम्भ हो गया। सन् 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू0 बुश प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह से भारत में मिले और परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुम्बई आकर भारत अमरीकी कारोबारी सम्मेलन को सम्बोधित किया और धीरे–धीरे दोनों देशों के सम्बन्ध इस स्थिति में पहुँच गये कि इनके बीच संयुक्त नौ सैनिक युद्धाभ्यास शुरु हुआ। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ और अमेरिकी ने 30 साल के लिए भारत से परमाणु कारोबार पर लगे स्थगन को हटा लिया। इसके बाद भारत ने भी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में सुधार पर कार्य करना आरम्भ कर दिया। 2010 में भारत व अमेरिका ने पहली बार इण्डिया यू0एस0 स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नींव डाली और इसी साल राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की प्रबल दावेदारी का समर्थन किया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

इस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत–अमेरिकी सम्बन्ध आरम्भ से ही ऐसे रहे जिसमें भारत कभी भी अमेरिका की गलत नीतियों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था और जब अमेरिका ने पाकिस्तान ने अपनी रूची दिखायी तो भारत ने भी रूस के साथ अपने सम्बन्धों को मधुर करने का प्रयास किया और यह सत्य है कि रूस इस स्थिति ने भारत के साथ खड़ा दिखा। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खुद को एक सक्षम देश के तौर पर स्थापित करने की दिशा ने आगे बढ़ा तो अमेरिका के पास भारत को महत्व देने के अलावा को कोई रास्ता नहीं था।

भारत अमेरिका के बीच वो विभिन्न मुद्दे जहाँ भारत अमेरिका से असहमत दिखा– ऐसे बहुत से मुद्दे रहे जिससे भारत ने अमेरिकी दबाव को सिरे से नकार दिया और खुद के राष्ट्रीय हित पर कार्य करना आरम्भ किया जैसे–

1. **परमाणु अप्रसार संधि (एन0पी0टी0 1968)**– परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया क्योंकि भारत का स्पष्ट कहना था कि यह एक भेदभाव पूर्ण संधि है। सन् 1968 में यह संधि अस्तित्व में आयी और 1970 में यह संधि लागू होता है जिसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकना परमाणु ऊर्जा के शान्ति पूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना परमाणु निरस्तीकरण और सामान्य तथा पूर्ण निरस्तीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण पर भी अंकुश लगाना था लेकिन भारत जिसने पहले ही कहा यह एक भेदभाव पूर्ण सन्धि है अतः उसने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया इस प्रकार एन0पी0टी0 के अन्तर्गत भारत को परमाणु सम्पन्न देश का दर्जा नहीं दिया गया इस सन्धि के अनुसार परमाणु सम्पन्न देश वह थे जिन्होंने सन् 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया था जबकि भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया। भारत ने स्पष्ट तर्क दिया कि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियारों का भण्डारण कर लिया है इसलिए सन्धि होने के बाद अब किसी नये देश को उसमें दाखिल नहीं होने देना भेदभावपूर्ण नीति है। भारत जिन विकसित देशों का नाम ले रहा था उसमें अमेरिका प्रमुख था जिसने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था। तो जाहिर तौर पर भारत ने एन0पी0टी0 पर हस्ताक्षर न करके अमेरिका से अपनी असहमति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तब स्पष्ट किया जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त देश की छवि बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था और यह भी भारत की विजय ही थी कि सन् 1970 में एन0पी0टी0 के लागू होने के बावजूद भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करके यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय हित उसके लिए सर्वोपरि है।

2. **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (CTBT) 1996**– सी0टी0बी0टी0 1996 में आयी लेकिन आज तक लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत सहित कई देशों ने इस सन्धि से अपनी सहमति नहीं दिखायी। भारत के समक्ष जिस तरह की घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति है भारत कभी भी सी0टी0बी0टी0 का समर्थन नहीं करेगा। भारत परमाणु परीक्षण अपनी स्वेच्छा से नहीं करेगा लेकिन परीक्षण फिर से शुरु करने का विकल्प वह जारी रखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत परमाणु परीक्षण में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के अनुपालन से कोई रुचि इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ भी वह अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रख रहा है विकसित देश परमाणु सम्पन्न है जिससे उनके हित सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है लेकिन भारत जो चाइना व पाकिस्तान जैसे देशों की अपरिपक्ता का दंश झेल रहा वह अपनी नागरिक की सुरक्षा को किसी सन्धि के द्वारा असुरक्षित नहीं कर सकता। भारत की इन्हीं सब कुछ नीतियों की वजह से भारत अमेरिकी सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण रहे भारत में उदारीकरण आयी तो अमेरिका को भी बदली

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

परिस्थितियों में यह एहसास होने लगा था कि भारत अपनी राग छोड़ने वाला नहीं है और वह अमेरिकी किसी भी दबाव के समक्ष तब नहीं झुका जब वह संघर्ष की स्थिति में था तो अब भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है विकासशील देशों में उसकी स्थिति उच्चतर की है तो वह क्यों अमेरिकी दबाव के समक्ष झुकेगा और यही से अमेरिका और भारत के बीच एक नये अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के सम्बन्ध– अगर वर्तमान समय में भारत–अमेरिकी सम्बन्ध की चर्चा की जाए तो यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय में विश्व पटल पर जिस तरह के बदलाव हुए हैं, उससे यह पूरी दुनिया बदल गई और इसी वजह से भारत अमेरिकी सम्बन्ध भी बदल गये। शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के सम्बन्ध अनिश्चित और अविश्वास से भरे थे जबकि अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय समझौते और निरन्तर सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भारत संयुक्त लक्ष्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है। दोनों देशों के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास इस स्थिति में उन्नत हुआ है कि अब अमेरिकी जहाज मरम्मत और रख रखाव के लिए तामिलनाडु जैसे भारतीय शिपयार्ड में रुकते हैं। इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता आज वर्तमान समय में लगभग 200 अरब डॉलर का है। इसके अतिरिक्त अगली पीढ़ी के लडाकू इंजनों के विनिर्माण केन्द्रों को भारत में स्थानान्तरित करने और सेमी कडंक्टर उत्पादन के लिए इसकी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे जो भू–आर्थिक सम्बन्धों की ओर इशारा कर रहे हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अमेरिकी सम्बन्ध जो कभी अविश्वास अनिश्चितता की धुरी पर टिके थे आज की दौर में अमेरिका भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद समकक्ष की तरह देख रहा और बराक अबोमा द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की मजबूत दाबेदारी की समर्थन इस बात का प्रमाण है कि आज वर्तमान समय में भारत की स्थिति अमेरिका के नजर में विटो–प्राप्त देशों से कम नहीं है। भारत की लोकतान्त्रिक और जवाबदेह राजनीति व्यवस्था के कारण ही अमेरिका भारत के प्रति इस तरह का रुख रखा जो बिना इस बात की चिन्ता किए कि चाइना भारत के लिए एक नकारात्मक रवैया रखता है।

उपरोक्त सभी बातें 21वीं सदी के विशेष सन्दर्भ में हो रही है लेकिन अगर आज की चर्चा की जाए तो ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के लिए एक नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल आयात कर रहा जिस पर अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। अमेरिका का यह आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा जो रूस को धन मुहैया करा रहा जिससे रूस युक्रेन से युद्ध कर रहा। यहाँ भी भारत का रूख हमेशा की तरह स्पष्ट है कि वह अमेरिका के किसी गलत दबाव के समक्ष नहीं झुकेगा। भारत जो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है अपनी खरीद रोकने का कोई संकेत नहीं दिया। भारत ने टैरिफ को अनुचित बताया तथा अपने 1.4 अरब लोगों की सुरक्षा के लिए तेल खरीदने के लिए ''सर्वोत्तम सौदा चुनना'' भारत का लक्ष्य होगा इसके प्रति भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखायी। इस प्रकार भारत हमेशा की तरह अमेरिका के अनुचित दबाव के समक्ष नहीं झुकने के लक्ष्य को पूर्ण किया।

निष्कर्ष – जैसा कि आरम्भ से ही स्पष्ट है कि भारत ने आजादी के तुरन्त बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रो से अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने पर कार्य किया लेकिन अमेरिका के साथ उसके रिश्ते लगभग चार दशक तक अनिश्चिता और अविश्वास से भरे रहे। नेहरु जी का यह कथन है कि ''अमेरिका के साथ कुछ गठबन्धन किया जा सकता है लेकिन अमेरिका की अधीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कथन का पालन भारत द्वारा आज तक किया जा रहा। एशिया में भारत की स्थिति का

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 01, January 2026

अन्दाजा अमेरिका को आरम्भ से ही था इसलिए अमेरिका ने भारत की प्रगति से उसका ध्यान अप्रत्यक्ष भटकाने के लिए पाकिस्तान का पोषण करता रहा कहीं न कहीं चाइना की भाँति अमेरिका भी यह मानता है कि भारत को पड़ोसी देशों के विवाद से उलझाना एक प्रकार से भारत की प्रगति में बाधक हो सकता है। भारत भी अमेरिका के पाकिस्तान पोषण से वाकिफ रहा इसलिए कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता से इतर सोवियत संघ के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना आरम्भ किया जो आज तक कायम है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत ने अमेरिका के ही भाँति अपने राष्ट्रीय हेतु से समझा नहीं किया फिर चाहे वह परमाणु अप्रसार सन्धि हो या सी0टी0बी0टी0 हो या आज वर्तमान परिदृश्य में ट्रंप शासन द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना हो भारत ने इस सभी स्थिति में अपने हित को सर्वोपरि रखा और नेहरु जी की कथन का पालन किया कि भारत कभी भी अमेरिका की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. फाड़िया, बी0एल0, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति
2. पीर बशारत भारत और अमेरिका : एक निश्चित दुविधा (सम्बन्ध)
3. https://www.bbc.comtranslate.google/news.com
4. खन्ना, वी0एन0, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

5- Mohan, C. Raja. *Impossible Allies: Nuclear India, United States and the Global Order*. Oxford University Press, 2006. ISBN: 9780195687359.

6- Tellis, Ashley J. *India as a New Global Power: An Action Agenda for the United States*. Carnegie Endowment for International Peace, 2005. ISBN: 9780870032211.

7- Ganguly, Sumit & Pardesi, Manjeet S. *Explaining Sixty Years of India–US Relations*. India Review, Routledge, 2009. ISBN: 9780415773383.

8- Scott, David. *India's Foreign Policy*. Polity Press, 2019. ISBN: 9781509537103.

9- Pant, Harsh V. *Contemporary Debates in Indian Foreign and Security Policy*. Palgrave Macmillan, 2016. ISBN: 9781137504346.

10- Cohen, Stephen P. *India: Emerging Power*. Brookings Institution Press, 2001. ISBN: 9780815719550.

11- Malone, David M., C. Raja Mohan & Srinath Raghavan (Eds.). *The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*. Oxford University Press, 2015. ISBN: 9780198743533.

12- Kapur, Devesh. *Diaspora, Development, and Democracy: The Domestic Impact of International Migration from India*. Princeton University Press, 2010. ISBN: 9780691144505.

13- Ministry of External Affairs, Government of India. *India–US Bilateral Relations*. Official Publications.

14- Clinton, Hillary. *Choices*. Simon & Schuster, 2014. ISBN: 9781451677726.